

**CLASS : 12th (Sr. Secondary)**

**4367/4317**

**Series : SS-M/2019**

Total No. of Printed Pages : 32

**SET : A, B, C & D**

**MARKING INSTRUCTIONS AND MODEL ANSWERS**

**SOCIOLOGY**

**ACADEMIC/OPEN**

(Only for Fresh/Re-appear Candidates)

उप-परीक्षक मूल्यांकन निर्देशों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करके उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करें। यदि परीक्षार्थी ने प्रश्न पूर्ण व सही हल किया है तो उसके पूर्ण अंक दें।

**General Instructions :**

- (i) Examiners are advised to go through the general as well as specific instructions before taking up evaluation of the answer-books.
- (ii) Instructions given in the marking scheme are to be followed strictly so that there may be uniformity in evaluation.
- (iii) Mistakes in the answers are to be underlined or encircled.
- (iv) Examiners need not hesitate in awarding full marks to the examinee if the answer/s is/are absolutely correct.

- (v) *Examiners are requested to ensure that every answer is seriously and honestly gone through before it is awarded mark/s. It will ensure the authenticity as their evaluation and enhance the reputation of the Institution.*
- (vi) *A question having parts is to be evaluated and awarded partwise.*
- (vii) *If an examinee writes an acceptable answer which is not given in the marking scheme, he or she may be awarded marks only after consultation with the head-examiner.*
- (viii) *If an examinee attempts an extra question, that answer deserving higher award should be retained and the other scored out.*
- (ix) *Word limit wherever prescribed, if violated up to 10%. On both sides, may be ignored. If the violation exceeds 10%, 1 mark may be deducted.*

- (x) *Head-examiners will approve the standard of marking of the examiners under them only after ensuring the non-violation of the instructions given in the marking scheme.*
- (xi) *Head-examiners and examiners are once again requested and advised to ensure the authenticity of their evaluation by going through the answers seriously, sincerely and honestly. The advice, if not headed to, will bring a bad name to them and the Institution.*
- 

### **महत्वपूर्ण निर्देश :**

- (i) अंक-योजना का उद्देश्य मूल्यांकन को अधिकाधिक वस्तुनिष्ठ बनाना है। अंक-योजना में दिए गए उत्तर-बिन्दु आंतिम नहीं हैं। ये सुझावात्मक एवं सांकेतिक हैं। यदि परीक्षार्थी ने इनसे भिन्न, किन्तु उपयुक्त उत्तर दिए हैं, तो उसे उपयुक्त अंक दिए जाएँ।
- (ii) शुद्ध, सार्थक एवं सटीक उत्तरों को यथायोग्य अधिमान दिए जाएँ।

- (iii) परीक्षार्थी द्वारा अपेक्षा के अनुसूचि सही उत्तर लिखने पर उसे पूर्णांक दिए जाएँ।
- (iv) वर्तनीगत अशुद्धियों एवं विषयांतर की स्थिति में अधिक अंक देकर प्रोत्साहित न करें।
- (v) भाषा-क्षमता एवं अभिव्यक्ति-कौशल पर ध्यान दिया जाए।
- (vi) मुख्य-परीक्षकों/उप-परीक्षकों को उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने के लिए केवल *Marking Instructions/Guidelines* दी जा रही है यदि मूल्यांकन निर्देश में किसी प्रकार की त्रुटि हो, प्रश्न का उत्तर स्पष्ट न हो, मूल्यांकन निर्देश में दिए गए उत्तर से अलग कोई और भी उत्तर सही हो तो परीक्षक, मुख्य-परीक्षक से विचार-विमर्श करके उस प्रश्न का मूल्यांकन अपने विवेक अनुसार करें।

**SET – A**

---

1. (i) सर्वेक्षण प्रणाली में
  - (ii) ड्रैक्टर, हारवेस्टर, टिलर
  - (iii) जर्मीदारी व्यवस्था के द्वारा
  - (iv) हरिजन नामक पत्र लिखा

( 5 )

**4367/4317**

(v) रंग है

(vi) (i) फलों का बाजार या थोक बाजार

(ii) रेलवे स्टेशन के पास का बाजार

(vii) विशाल और जटिल आधुनिक समाज में

(viii) साक्षात्कार पद्धति में

(ix) अवैयक्तिक अथवा सामूहिक विभिन्नतायें।

(x) संविधान

(xi) 1930 में

(xii) उपरोक्त सभी

(xiii) उपरोक्त सभी

(xiv) रेडियो

(xv) उपरोक्त सभी को

(xvi) सामाजिक आन्दोलन में

$1 \times 16 = 16$

**4367/4317/(Set : A, B, C & D)**

P. T. O.

- 2. उत्पादन विधि** – विशेष उत्पादन सम्बन्धों से बनती है और अंततः वह एक विशिष्ट वर्ग संरचना का निर्माण करती है। 2
- 3. जन्म और व्यवसाय** – की बदौलत ब्राह्मणों को सबसे उच्च और दलितों को सबसे निम्न स्थिति दी गई है। 2
- 4. राष्ट्र** – एक ऐसा समुदाय जो अपने आपको एक समुदाय मानता है और अनेक साझा विशिष्टताओं जैसे : साझी भाषा, भौगोलिक स्थिति, इतिहास, धर्म, प्रजाति, राजनीतिक आकांक्षाओं पर आधारित होता है। 2
- 5. प्रदत्त पहचान** – किसी परिवार या समुदाय अथवा देश में उत्पन्न होने पर मिली पहचान ‘प्रदत्त’ पहचान कही जाती है। 2
- 6. औपनिवेशिक भारत में** – चेन्नई से ब्रिटेन को कहवा, चीनी, नील और कपास आदि निर्यात किया जाता था। 2
- 7. जनसंख्या संवृद्धि दर** – का तात्पर्य है जन्म-दर और मृत्यु-दर के बीच का अन्तर है। जिसे प्राकृतिक वृद्धि दर भी कहते हैं। 2
- 8. भारत में विविधता के** – कारण उत्पन्न बड़ी-बड़ी चुनौतियाँ जैसे - क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिकता और जातीयता आदि हैं। 2

- 9. अर्थव्यवस्थायें** - समाज में 'रची-बसी हैं' इस विचार को समाजशास्त्रियों ने उदाहरण देकर समझाया है। पहला उदाहरण है, एक 'साप्ताहिक आदिवासी' हाट का और दूसरा है एक 'पारम्परिक व्यापारिक समुदाय' और भारत के उपनिवेशिक दौर में उसका लेन-देन का तंत्र। 2
- 10. क्रान्तिकारी सामाजिक आन्दोलन** - वे आन्दोलन हैं, जो सामाजिक सम्बन्धों के आमूल रूपांतरण का प्रयास करते हैं, प्रायः राजसत्ता पर अधिकार के द्वारा। 2
- 11. भारत में आंदोलन** - महिलाओं, कृषकों, दलितों, आदिवासियों तथा अन्य सभी प्रकार के सामाजिक आन्दोलन हुये हैं। 2
- 12. उत्तर प्रदेश** - के जाट और राजपूत आदि प्रबल भूस्वामी समूहों के उदाहरण हैं। 2
- 13. संविधान के अनुच्छेद 21 में** - जीवन और स्वतन्त्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त जीवन के लिये अनिवार्य गुणवत्ता, जीवनयापन के लिए साधन, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और गरिमा की व्याख्या करता है। 2
- 14. सामाजिक बहिष्कार** - वह तौर-तरीके हैं जिनके जरिए किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह घुलने-मिलने से रोका

जाता है। यह उन सभी कारकों पर ध्यान दिलाता है जो व्यक्ति या समूह को उन अवसरों से बचाते हैं जो अधिकांश जनसंख्या के लिए खुले होते हैं। भरपूर तथा क्रियाशील जीवन जीने के लिए, व्यक्ति को जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की ज़रूरत होती है। सामाजिक भेदभाव अचानक नहीं बल्कि व्यवस्थित तरीके से होता है। यह सामाज की संरचनात्मक विशेषताओं का परिणाम है।

यहाँ इस बात पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि सामाजिक बहिष्कार अनैच्छिक होता है। 4

**15. पंचायती राज संस्था :** की संरचना एक पिरामिड की भाँति है। संरचना के आधार पर लोकतन्त्र की इकाई के रूप में ग्राम सभा स्थित होती हैं। इसमें पूरे गाँव के सभी नागरिक शामिल होते हैं। स्थानीय सरकार का चुनाव इसी आम सभा के द्वारा किया जाता है। ग्राम सभा परिचर्चा और ग्रामीण स्तर के विकासात्मक कार्यों के लिये एक मंच उपलब्ध कराती है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में निर्बलों की भागीदारी के लिये एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है।

संविधान के 73वें संशोधन ने बीस लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायतीराज प्रणाली लागू की और प्रत्येक 5 वर्ष बाद इसके सदस्यों का चुनाव अनिवार्य किया गया। 4

**16. प्रेक्षण** – जब एक शोधकर्ता प्रत्यक्ष भागीदारी द्वारा सूचनाएँ एकत्र करता है और किसी एक समूह, जनजाति या समुदाय का निरीक्षण करता है तो उसके इस कार्य को प्रेक्षण पद्धति कहते हैं। इस पद्धति द्वारा एक शोधकर्ता कुछ उन व्यवहारों और प्रतिमानों के बारे में पता लगाता है जिन्हें कि अन्य शोध प्रविधियों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अनेक मामलों में, शोधकर्ता वस्तु स्थिति समझने के लिये कुछ समय तक व्यक्तिगत रूप से किसी समूह में सम्मिलित हो जाते हैं।

प्रेक्षण बहुत अधिक समय लेने वाली शोध पद्धति है। अक्सर शोधकर्ता को महत्वपूर्ण घटनाओं के अध्ययन के लिए काफी इन्तज़ार करना पड़ सकता है। 4

**17. युद्ध और विपदाओं में** – यह एक रोचक तथ्य है कि युद्धों और विपदाओं के कारण आकशवाणी के क्रियाकलापों में विस्तार हुआ है। 1962 में जब चीन के साथ युद्ध हुआ तो आकशवाणी ने एक दैनिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिये ‘वार्ता’ इकाई की स्थापना की। अगस्त 1971 में, जब बांग्लादेश का संकट मंडराने लगा तो समाचार सेवा प्रभाग ने 6 बजे प्रातः से मध्यरात्रि तक हर घण्टे समाचार प्रसारण चालू किया। फिर 1991 के एक और संकट में राजीव गांधी की नृशंस हत्या के बाद ही आकशवाणी ने चौबीसों घण्टे बुलेटिन प्रस्तुत करने का एक और कदम उठाया। 4

**18. स्वतन्त्र भारत के प्रारम्भिक वर्षों में -** रुई, जूट, कोयला खाने एवम् रेलवे भारत के प्रथम आधुनिक उद्योग थे। स्वतन्त्रता के बाद सरकार ने आर्थिकी को 'प्रभावशाली ऊँचाईयों' पर रखा। इसमें सुरक्षा, परिवहन तथा संचार, ऊर्जा खनन एवम् अन्य परियोजनाओं को शामिल किया गया जिन्हें करने के लिये सरकार ही सक्षम थी और यह निजी उद्योगों के फलने-फूलने के लिये आवश्यक भी न था। भारत की मिश्रित आर्थिक नीति में कुछ क्षेत्र सरकार के लिये आरक्षित थे जबकि कुछ निजी क्षेत्रों के लिये खुले थे। स्वतन्त्रता के पहले उद्योग मुख्यतः बंदरगाह वाले शहरों तक सीमित थे। लेकिन उसके बाद अन्य स्थानों को महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र बनाया गया। सरकार अन्य छोटे पैमाने के उद्योगों को भी प्रोत्साहित कर रही है।

4

**19. प्रबल जाति शब्द का -** प्रयोग ऐसी जातियों का उल्लेख करने के लिये किया जाता है जिनकी जनसंख्या काफी बड़ी होती थी और जिन्हें स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद किए गए आंशिक भूमि-सुधारों द्वारा भूमि के अधिकार प्रदान किये गये थे। इन भूमि-सुधारों ने पहले के दावेदारों से अधिकार छीन लिये थे। ये दावेदार ऊँची जातियों के ऐसे सदस्य होते थे जो इस अर्थ में 'अनुपस्थित यानी दूरवासी जर्मीदार' थे कि वे अपना लगान वसूल करने के अलावा कृषिक अर्थव्यवस्था में कोई भूमिका अदा नहीं करते थे। इन प्रबल जातियों के कुछ उदाहरण हैं; बिहार और उत्तर प्रदेश के यादव, कर्नाटक के लोककलिंग, महाराष्ट्र के मराठे आदि।

4

**SET – B**

---

1. (i) सर्वेक्षण, साक्षात्कार, अवलोकन आदि
- (ii) महिलायें, दलित एवम् अन्य उत्पीड़ित जातियाँ, जनजातियाँ
- (iii) 1873 में
- (iv) हरिजन नामक पत्र से
- (v) मार्च 1950 में
- (vi) परिवार से बाजार तक की संस्थायें
- (vii) प्रतिनिधिक लोकतन्त्र
- (viii) प्रश्नावली तैयार करनी चाहिये
- (ix) 1851 में
- (x) अपना अस्तित्व सक्रिय बनाये रखने के लिये
- (xi) वैश्य
- (xii) पंचम को
- (xiii) जातिवाद

( 12 )

**4367/4317**

(xiv) जाति

(xv) उपरोक्त सभी

(xvi) समाचार-पत्र

$1 \times 16 = 16$

**2. परियोजना कार्य -**

$1 + 1 = 2$

(i) व्यवहारिकता

(ii) मनोवैज्ञानिक संतुष्टि

(iii) सामाजिक भावना का विकास

**3. औद्योगिकरण -** एक नए सामाजिक समूहों और नये सामाजिक सम्बन्धों के उद्भव और विकास की कहानी है। 2

**4. समुदाय -** किसी भी ऐसे विशिष्ट समूह के लिये प्रयुक्त सामान्य शब्द, जिसके सदस्य सचेतन रूप से मान्यता प्राप्त समानताओं और नातेदारी के बंधनों, भाषा, संस्कृति आदि के कारण आपस में जुड़े हों। 2

**5. प्रदत्त पहचानों की -** एक विशेषता यह होती है कि वे सर्वव्यापी होती हैं। 2

**4367/4317/(Set : A, B, C & D)**

**6. मुद्दे जिन्होंने जनजातीय आन्दोलनों -**

- (i) भूमि विशेष रूप से वनों जैसे अत्यन्त महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधनों पर नियन्त्रण से सम्बन्धित मुद्दे।
- (ii) नृजातीय-सांस्कृतिक पहचान के मामलों से सम्बन्धित मुद्दे। 2

**7. ऋणात्मक संवृद्धि दर -** जब किसी समाज में उनका प्रजनन शक्ति स्तर प्रतिस्थापन दर से नीचा रहता है तब उसे ऋणात्मक संवृद्धि दर कहा जाता है। 2

**8. सन् 1951 से -** अब तक निम्नानुसार जनगणना कार्य हुआ है : 2

1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 तथा 2011.

**9. विनिमय का बिल -** व्यापारियों द्वारा लम्बी दूरी के व्यापार में इस्तेमाल किया जाने वाला एक कर्ज पत्र है जिसे देश में एक कोने से एक व्यापारी द्वारा जारी हुई हुंडी दूसरे कोने में व्यापारी द्वारा स्वीकार की जाती थी। 2

**10. 19वीं सदी के दो समाज सुधारक :**

1 + 1 = 2

- (i) रानाडे

- (ii) राम मोहन

**11. अदृश्य हाथ** - समाज के हित में काम करने वाली अदृश्य शक्ति अर्थात् एक अदृश्य बल जो व्यापार में व्यक्तियों के लाभ की प्रकृति को समाज के लाभ में बदल देता है। इस बल को 'स्मिथ' ने 'अदृश्य हाथ' का नाम दिया है। 2

**12. आधुनिक और समुद्धिशील** : भारत की नींव वृहद लौह-इस्पात उत्पादक उद्योगों या विशाल बाँधों और विद्युतशक्ति के केन्द्रों पर रखी गई। 2

**13. खाली जगहों का** - प्रयोग जैसे कि सड़क किनारे की खाली जगह में छिटपुट सामान बेचने वाले खड़े होते हैं, छोटी-मोटी काम चलाऊ दुकानें होती हैं अथवा वाहन खड़े होते हैं। इसके अतिरिक्त विवाह या धार्मिक समारोहों के लिये इसका प्रयोग किया जाता है। 2

**14. प्रजनन दर** : से तात्पर्य बच्चा उत्पन्न करने योग्य आयु समूह की स्त्रियों द्वारा जीवित बच्चों को जन्म देना है। प्रजननता-दर की गणना एक वर्ष में समग्र जनसंख्या के प्रति 1,000 बच्चा उत्पन्न करने योग्य आयु-समूह की स्त्रियों द्वारा जन्मे जीवित बच्चों के आधार पर की जाती है। हमारे देश में बच्चा उत्पन्न करने की आयु सीमा 15 से 49 वर्ष मानी जाती है। किसी भी देश की प्रजननता का स्तर निम्न तथ्यों से प्रभावित व सम्बन्धित होता है :

(i) देश में प्रजनन योग्य आयु में स्त्रियों की संख्या क्या है ?

(ii) उन स्त्रियों में विवाहित स्त्रियों की संख्या क्या है ?

(iii) स्त्रियों में प्रजनन सामर्थ्य कितना है ? 4

**15. आधुनिकता** - का अर्थ हम इस रूप में समझ पाते हैं कि इसके समक्ष सीमित संकीर्ण स्थानीय दृष्टिकोण कमज़ोर पड़ जाते हैं और सार्वभौमिक प्रतिबद्धता और विश्वजनित दृष्टिकोण ज्यादा प्रभावशाली होता है। इसमें उपयोगिता, गणना और विज्ञान की सत्यता को भावुकता, धार्मिक पवित्रता और अवैज्ञानिक तत्त्वों के स्थान पर महत्व दिया जाता है। इसके प्रभाव में सामाजिक तथा राजनीतिक स्तर पर व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाती है न कि समूह को; इसके मूल्यों के मुताबिक मनुष्य ऐसे संगठन में रहते और काम करते हैं जिसका चयन जन्म के आधार पर नहीं बल्कि इच्छा के आधार पर होता है। 4

**16. संविधान द्वारा प्रदत्त** - सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारतीय संविधान द्वारा दिये गये प्रमुख अधिकारों में से एक है। इसका अर्थ यह है कि हम स्वयं अपने चुने हुये प्रतिनिधियों के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा शासित नहीं हो सकते। यह अधिकार औपनिवेशिक शासन के दिनों से मौलिक रूप से भिन्न है। हालांकि ब्रिटेन में भी सभी को मतदान का अधिकार नहीं था। मतदान का अधिकार सम्पत्ति के स्वामियों तक सीमित था। सन् 1839 में 12-50 लाख लोगों ने जब चार्टर पर हस्ताक्षर करके सम्पत्तिहीन होने

पर भी चुनाव में खड़े होने के अधिकार की माँग की। सन् 1842 में उक्त आन्दोलन ने 3,25,000 हस्ताक्षर एकत्रित किये। फिर भी प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् ही सन् 1918 में, 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी पुरुषों, 30 वर्ष से अधिक आयु की विवाहिताओं, गृह स्वामिनियों तथा विश्वविद्यालयी स्नातक महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला।

4

**17. स्त्री-पुरुष तुलना** - नामक पुस्तक एक महाराष्ट्रीय गृहिणी ताराबाई शिंडे द्वारा लिखी गई थी, जिसमें पुरुष प्रधान समाज द्वारा अपनाए गए दोहरे मापदंडों का विरोध किया गया था। एक जवान ब्राह्मण विधवा को न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया गया था, विधवा का अपराध यह था कि उसने अपने नवजात शिशु की हत्या इसलिए कर दी थी क्योंकि वह उसकी नाजायज़ संतान था; लेकिन जिस पुरुष का वह बच्चा था उसका पता लगाने या उसे दण्ड देने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। जब स्त्री-पुरुष तुलना प्रकाशित हुई तो समाज में एक खलबली सी मच गई।

4

**18. निगम संस्कृति** - प्रबन्धन सिद्धान्त की एक ऐसी शाखा है, जो किसी फर्म के सभी सदस्यों को साथ लेकर एक अद्भुत संगठनात्मक संस्कृति के निर्माण के माध्यम से उत्पादकता और प्रतियोगितात्मकता को बढ़ावा देने का प्रयत्न करती है। ऐसा सोचा जाता है कि एक गतिशील निगम संस्कृति - जिसमें कम्पनी के

कार्यक्रम रीतियाँ एवम् परम्पराएँ शामिल होती हैं, कर्मचारियों में वफादारी की भावना को बढ़ाती हैं और समूह एकता को प्रोत्साहित करती हैं। वह यह भी बताती है कि काम करने का तरीका क्या है और उत्पादों को कैसे बढ़ावा दिया जाये और उनको कैसे पैक किया जाए।

4

**19. प्रतिरोधी आन्दोलन :** सामाजिक आन्दोलन प्रायः किसी जनहित के मामले में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं। परन्तु कभी-कभी यथापूर्व स्थिति बनाये रखने के लिये प्रतिरोधी आन्दोलन जन्म ले लेते हैं। ऐसे प्रतिरोधी आन्दोलनों के कई उदाहरण हैं। जब राजा राम मोहन राय ने सती-प्रथा का विरोध किया तथा ब्रह्म समाज की स्थापना की तो सती प्रथा के प्रतिरक्षकों ने धर्मसभा स्थापित की तथा अंग्रेजों को सती के विरुद्ध कानून न बनाने के लिये याचिका दी।

जब सुधारवादियों ने बालिकाओं के लिये शिक्षा की माँग की तो बहुत से लोगों ने यह कहकर इसका विरोध किया कि यह समाज के लिये विनाशकारी होगा।

जब सुधारकों ने विधवा पुनर्विवाह का प्रचार किया तो उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया। इस प्रकार के अन्य बहुत से उदाहरण देखे व सुनें जा सकते हैं।

4

**SET – C**

---

**1. (i) जाति**

- (ii) 26 नवम्बर 1949 को
- (iii) राज्य की
- (iv) आर्थिक स्वतन्त्रता और सामाजिक न्याय भी है
- (v) मद्रास, बंबई, कलकत्ता
- (vi) कृषि उत्पादन कम होने लगा
- (vii) गैस, मिक्सिंग, प्रेशर कुकर, कपड़े धोने की मशीन
- (viii) टेलिविज़न, मोटर साइकिल, गलीचा
- (ix) 19वीं शताब्दी के साथ
- (x) खुला मैदान, पैदल पटरी, आवासी बस्तियों में खाली पड़े भूखण्ड आदि
- (xi) लोकतन्त्र
- (xii) उपरोक्त सभी

(xiii) फ्रांसिसी

(xiv) पश्चिमी

(xv) उपरोक्त सभी

(xvi) भारत सरकार के प्रस्ताव पर  $1 \times 16 = 16$

**2.** संस्कृतिकरण - डॉक्टर एम० एन० श्रीनिवास कृत एक ऐसी अवधारणा है जिसमें निम्न जाति या समूह उच्च जातियों विशेषकर द्विंज जाति की जीवन पद्धति, अनुष्ठान, मूल्य, आदर्श, विचारधाराओं का अनुकरण करते हैं। 2

**3.** उच्चतम न्यायालय - देश का सबसे बड़ा न्यायालय है और संविधान की व्याख्या करने का अधिकार केवल इसी न्यायालय को है। 2

**4.** उदारीकरण की नीति - सन् 1990 के दशक से सरकार ने इस नीति को अपनाया है। इस नीति के अन्तर्गत पहले से ही सरकार के लिये आरक्षित क्षेत्रों के लिये विदेशी फर्मों को निवेश के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है। 2

**5.** साक्षात्कार पद्धति - का एक लाभ यह भी है कि उत्तरदाता से उसके द्वारा दिये गये उत्तर को स्पष्ट करने के लिये कहा जा सकता है। 2

**6. राज्य शब्द** - का अर्थ एक इस प्रकार की समिति से है कि यह कानून व शासन के अधिकार द्वारा कार्य करती है और इसे एक निश्चित क्षेत्र के अन्तर्गत सामाजिक व्यवस्था बनाये रखने के लिये सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होते हैं।

2

**7. घटक जो भारत की** - एकता व अखण्डता को हानि पहुँचाने में लगी हैं; साम्प्रदायिक दंगे, क्षेत्रीय स्वायत्तता की माँगें, जातिगत लड़ाई-झगड़े आदि हैं। यू० पी० के बुलन्दशहर की घटना शायद इसी ओर संकेत करती है।

2

**8. सामाजिक बहिष्कार** - वह तौर-तरीके हैं जिनके जरिये किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह घुलने-मिलने से रोका जाता है व अलग रखा जाता है।

2

**9. साक्षात्कार पद्धति** - की एक कमजोरी है कि इसमें केवल व्यक्तियों के एक चयनित समूह के विचारों को ही प्रस्तुत किया जाता है। HSSC द्वारा वर्तमान में लिये जा रहे साक्षात्कार इसके उपयुक्त उदाहरण माने जा सकते हैं।

2

- 10.** पुष्कर - राजस्थान में एक वार्षिक प्रसिद्ध मेला लगता है जिसमें दूर-दराज से, व्यापारी और पशुचारी ऊँटों और अन्य पशुओं को बेचने और खरीदने आते हैं। ये अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े पर्यटन स्थल के नाम से जाना जाता है। 2
- 11.** भारत में भूमण्डलीकरण - के युग की शुरुआत मुख्यतः राज्य स्तरीय विकास से उदारवाद जैसी आर्थिक नीति के परिवर्तन की वजह से हुआ। 2
- 12.** भारत एक महान - सांस्कृतिक विविधता वाला राष्ट्र है तो हमारा तात्पर्य यह होता है कि यहाँ अनेक प्रकार के सामाजिक समूह एवम् समुदाय निवास करते हैं; जिन्हें भाषा, धर्म, पंथ, प्रजाति द्वारा परिभाषित किया जाता है। 2
- 13.** कृत्रिम अवरोध - जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित अथवा सीमित करने के लिये अपनाये गये उपाय जैसे : बड़ी उम्र में विवाह, यौन संयम अथवा ब्रह्मचर्य का पालन। 2
- 14.** **1901** की जनगणना - हरबर्ट रिसले के निर्देशन में की गई जनगणना विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी क्योंकि इस जनगणना के अन्तर्गत जाति के अधिक्रम के बारे में जानकारी इकट्ठी करने का प्रयत्न किया गया अर्थात् क्षेत्र में किस जाति को अन्य जातियों की

तुलना में सामाजिक दृष्टि से कितना ऊँचा या नीचा स्थान प्राप्त है और तदनुसार श्रेणीक्रम में प्रत्येक जाति की स्थिति निर्धारित कर दी गई। जाति के सामाजिक बोध पर इस प्रयास का गहरा प्रभाव पड़ा और विभिन्न जातियों के प्रतिनिधियों द्वारा जनगणना आयुक्त के पास सैकड़ों याचिकायें भेजी गई जिनमें उन्होंने सामाजिक क्रम में अपनी जाति को ऊँचा स्थान देने की माँग की थी। कुल मिलाकर यह गणना जाति के नये जीवन की शुरुआत साबित हुई। 4

**15. अस्पृश्यता** - जिसे आम बोल-चाल की भाषा में ‘छुआछूत’ कहा जाता है; जाति-व्यवस्था का एक अत्यन्त घृणित एवम् दूषित पहलु है, जो धार्मिक एवम् कर्मकांडीय दृष्टि से शुद्धता एवम् अशुद्धता के पैमाने पर सबसे नीची मानी जाने वाली जातियों के सदस्यों के विरुद्ध अत्यन्त कठोर सामाजिक दण्डों का विधान करता है। अछूत मानी जाने वाली जातियों का जाति सोपान में कोई स्थान ही नहीं है। उन्हें तो इतना अधिक ‘अशुद्ध’ एवं अपवित्र माना जाता है कि उन्हें छू जाने मात्र से व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है और उसे फिर से शुद्धिकरण के लिये कई शुद्धिकरण क्रियायें करनी होती हैं। 4

**16. आधुनिकरण** - की अवधारणा का प्रयोग विशेषतौर पर समाज में होने वाले परिवर्तनों के कारण पश्चिमी देशों में आए परिवर्तनों को समझाने के लिये किया गया है। इसके साथ ही, आधुनिकीकरण का

प्रयोग उपनिवेशी एवं विकासशील देशों में होने वाले परिवर्तनों को समझाने के लिये किया गया है।

वास्तव में, आधुनिकीकरण की अवधारणा का सम्बन्ध वैज्ञानिक मूल्यों से है। यह किसी समाज और संस्कृति के घेरे में बन्द नहीं है। आधुनिकरण के आयामों को कई स्तरों पर देखा जा सकता है, जैसे - व्यक्ति, समूह एवं समस्त समाज। अतः आधुनिकीकरण एक प्रकार की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं की ओर परिवर्तन की प्रक्रिया है।

4

**17. जनजातीय क्षेत्रों में -** प्रारम्भिक स्तर के लोकतान्त्रिक कार्यों की अपनी समृद्ध परम्परा रही है। हम मेघालय से सम्बन्धित एक उदाहरण लें। गारो, खासी, जयंतिया, तीनों ही आदिवासी जातियों की सैकड़ों साल पुरानी अपनी राजनीतिक संस्थायें रही हैं। ये राजनीतिक संस्थायें इतनी सुविकसित थीं कि ग्राम, वंश और राज्य के स्तर पर ये बड़ी कुशलता से कार्य करती थीं। उदाहरणार्थ, खासियों की पारम्परिक राजनीतिक प्रणाली में प्रत्येक वंश की अपनी परिषद होती थी जिसे 'दरबार कुक' कहा जाता था और जो उस वंश के मुखिया के निर्देशन में कार्य करता था।

4

**18. इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था -** एक ऐसा कारक है जो आर्थिक भूमंडलीकरण को सहारा देता है। कम्प्यूटर के माउस को दबाने

मात्र से बैंक, निगम, निधि प्रबंधक और निवेशकर्ता अपनी निधि को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इधर से उधर भेज सकते हैं। हालांकि इस प्रकार क्षण भर में इलेक्ट्रॉनिक 'मुद्रा' भेजने का यह तरीका बहुत खतरनाक भी है। भारत में इसकी चर्चा स्टॉक एक्सचेंज में होने वाले उतार-चढ़ाव के संदर्भ में की जाती है। यह उतार-चढ़ाव विदेशी निवेशकों द्वारा मुनाफे के लिये अचानक बड़ी मात्रा में स्टॉक खरीदने या बेचने के कारण आता है। ऐसे सौदे संचार क्रान्ति की बदौलत ही संभव हुए हैं।

4

**19.** आजादी के बाद विशेषकर - ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक संबंधों की प्रकृति में अनेक प्रभावशाली रूपांतरण हुये, विशेषतः उन क्षेत्रों में जहाँ हरित क्रान्ति लागू हुई। ये बदलाव थे :

- (i) गहन कृषि के कारण कृषि मजदूरों की बढ़ौतरी।
- (ii) नगद भुगतान की शुरुआत।
- (iii) 'मुक्त' दिहाड़ी मजदूरों के वर्ग का उदय।
- (iv) पारम्परिक बंधनों में शिथिलता अथवा भू-स्वामी एवम् किसान या कृषि मजदूरों के मध्य पुश्तैनी सम्बन्धों में कमी होना। इन सम्बन्धों का वर्णन समाजशास्त्री जॉन ब्रेमन ने 'संरक्षण से शोषण' की बदलाव में किया था।

4

**SET – D**

---

**1. (i) साक्षात्कार पद्धति में**

(ii) राजस्थान उत्तर प्रदेश

(iii) व्यवसाय से

(iv) खुले व्यापार का

(v) युवा पीढ़ी

(vi) क्रय-विक्रय

(vii) एल्फ्रेड गेल ने

(viii) संविधान ने

(ix) एमिल दुखाइम की

(x) स्वाभाविक भिन्नता को

(xi) राज्य

(xii) राज्य

(xiii) सामाजिक समरसता

(xiv) भारत

(xv) जूट (पटसन)

(xvi) उपरोक्त सभी को

 $1 \times 16 = 16$ 

- 2.** विनिवेश - सरकार सार्वजनिक कंपनियों के अपने शेयर्स को निजी क्षेत्र की कंपनियों को बेचने का प्रयास करती है तो उसे विनिवेश कहा जाता है। 2

- 3.** सामाजिक आन्दोलन के - प्रतिदानात्मक, सुधारवादी, क्रान्तिकारी।

 $1 + 1 = 2$ 

- 4.** ऐतिहासिक पद्धति - समाजों, सभ्यताओं, समुदायों घटनाओं, संस्थानों व समस्याओं के विकास क्रम के अध्ययन करने की पद्धति है जिसका प्रयोग उत्पत्ति, विकास से सम्बन्धित अध्ययनों में किया जाता है। 2

- 5.** कानून और न्याय में -

- (i) कानून का सार इसकी शक्ति है जबकि न्याय का सार निष्पक्षता है।

(ii) कानून में बल प्रयोग के संचरण के माध्यमों का प्रयोग होता है जबकि न्याय संविधान पर आश्रित होता है।

(iii) कानून के पीछे राज्य की शक्ति निहित होती है। जबकि न्याय के पीछे ऐसी कोई शक्ति नहीं होती। 2

**6. जातिवाद** - कुछ जातियों द्वारा कुछ अन्य जातियों का बहिष्कार या उत्पीड़न है। 2

**7. 1901 और 1951 के बीच** - 1911, 1921, 1931, 1941 के वर्षों में जनगणना कार्य सम्पन्न कराया गया। 2

**8. अन्तर्राष्ट्रीय विवाह का -**

(i) युवक युवतियों का प्यार परवान चढ़ रहा है।

(ii) जाति-पाति की दीवारें ढह रही हैं। सबसे बड़ा लाभ राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार के विवाह करने वालों को घर बसाने के लिये आर्थिक सहायता प्रदान करना है। 2

**9. सावित्रीबाई फुले** - देश में बालिकाओं के लिये बने पहले विद्यालय की पहली प्रधान अध्यापिका थीं। इन्होंने अपना पूरा जीवन शूद्रों और अति शूद्रों को शिक्षा अर्पण करने में लगा दिया। 2

**10. कार्यशील वर्ग** – जनसंख्या का वह भाग है जो श्रम के द्वारा अपना व अपने परिवार का भरण-पोषण व अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसमें आमतौर पर 15 से 64 वर्ष की आयु के लोग होते हैं। 2

**11. उपनिवेशकाल के दौरान** – ही मारवाड़ी एक सफल व्यापारिक समुदाय बने, जब उन्होंने उपनिवेशिक शहरों जैसे कलकत्ता में मिलने वाले नए सुअवसरों का लाभ उठाया और व्यापार और साहूकारी जारी रखाने के लिये देश के सभी भागों में बस गये। 2

**12. भारत के चार** – आधुनिक उद्योग रुई, जूट, कोयला खाने एवं रेलवे थे। 2

**13. भारत के दो प्रमुख** – धार्मिक समुदाय हिन्दू 80.5% तथा मुस्लिम 13.4% हैं। 2

**14. जनसंख्या की आयु संरचना** – भारत में युवा जनसंख्या की अधिकता है यानि भारत में अधिकांश जनता 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की है। भारत में औसत आयु भी विश्व के अधिकांश देशों से कम है। 15 वर्ष की आयु वर्ग में निरन्तर कमी आ रही है। जहाँ 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की प्रतिशतता में वृद्धि हो रही है वहाँ +65 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या अपेक्षाकृत बहुत कम है। परन्तु

अब यह सम्भावना व्यक्त की जा रही है कि अपने वाले समय में 65 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या में वृद्धि होगी। जबकि 0-14 वर्ष के आयु वर्ग में कमी आएगी।

4

- 15. सामाजिक विषमता** - प्रत्येक समाज में हर व्यक्ति की सामाजिक प्रस्थिति एकसमान नहीं होती है। समाज में कुछ लोगों के पास तो धन, सम्पत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, सत्ता और शक्ति जैसे साधनों की अधिकता होती है तो दूसरी ओर कुछ लोगों के पास इनका नितान्त अभाव रहता है तो कुछ लोगों की स्थिति बीच की रहती है। सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुँच की पद्धति ही साधारणतया सामाजिक विषमता कहलाती है। कुछ सामाजिक विषमताएँ व्यक्तियों के बीच स्वाभाविक भिन्नता को प्रतिबिंबित करती हैं। उदाहरणस्वरूप उनकी योग्यता एवम् प्रयास में भिन्नता।

अंतः हम यूँ भी कह सकते हैं कि सामाजिक विषमता व्यक्तियों के बीच 'प्राकृतिक' भिन्नता की वजह से नहीं है। बल्कि यह उस समाज द्वारा उत्पन्न की जाती है, जिसमें वे रहते हैं।

4

- 16. अर्थव्यवस्था के उदारीकरण** - का अर्थ था भारतीय व्यापार को नियमित करने वाले नियमों और वित्तीय नियमनों को हटा देना। इन उपायों को 'आर्थिक-सुधार' भी कहा जाता है। ये सुधार क्या हैं ? जुलाई 1991 से, भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपने सभी प्रमुख क्षेत्रों (कृषि, उद्योग, व्यापार, विदेश निवेश और प्रौद्योगिकी,

सार्वजनिक क्षेत्र, वित्तीय संस्थायें आदि) में सुधारों की एक लम्बी शृंखला देखी है। इसके पीछे मूल अवधारणा यह थी कि भूमंडलीय बाजार में पहले से अधिक समावेश करना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये लाभकारी सिद्ध होगा।

4

- 17. अनक्वाइट बुड्स :** पर्यावरण विद्/संरक्षक रामचन्द्र गुहा की प्रसिद्ध पुस्तक है। यह पारिस्थिकीय आन्दोलन से जुड़े विभिन्न मुद्दों को जानने के लिये एक उदाहरण को प्रस्तुत करती है। अनक्वाइट बुड्स के अनुसार गाँववासी अपने गाँव के निकट के ओक तथा रोहोडैंड्रोन के जंगलों को बचाने के लिये एक साथ आगे आये। सरकारी जंगल के ठेकेदार पेड़ों को काटने के लिये आगे आये तो गाँववासी जिनमें अधिकतर महिलायें शामिल थीं वो पेड़ों को काटने से रोकने के लिये आगे आईं। क्योंकि गाँववासियों के जीवन निर्वाह का प्रश्न दाँव पर था। इस संघर्ष ने गरीब गाँववासियों की आजीविका की आवश्यकताओं को बेचकर राजस्व करने की सरकार की इच्छा के समक्ष खड़ा कर दिया।

4

- 18. मजदूरों के बड़े पैमाने पर -** प्रवासी कृषि मजदूरों की बढ़ौतरी ग्रामीण समाज का एक अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो कृषि के व्यवसाय के व्यापारीकरण से जुड़ा है। मजदूरों अथवा पहरेदारों तथा भूस्वामियों के बीच संरक्षण का पारंपरिक सम्बन्ध टूटने से तथा

पंजाब जैसे हरित क्रान्ति के सम्पन्न क्षेत्रों में कृषि की माँग बढ़ने से मौसमी पलायन का प्रतिमान उभरा।

मजदूरों के बड़े पैमाने पर संचार से ग्रामीण समाज, दोनों ही भेजने वाले तथा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों पर अनेक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े हैं। उदाहरण के लिये निर्धन क्षेत्रों में, जहाँ परिवार के पुरुष सदस्य वर्ष का अधिकतर हिस्सा गाँव के बाहर काम करने में बिताते हैं, कृषि मूल रूप से महिलाओं का कार्य बन गया है। जिससे कृषि-मजदूरों का महिलाकरण हो रहा है।

4

**19. सर्वेक्षण प्रणाली** - के द्वारा किसी सामाजिक समूह या सामाजिक जीवन के किसी पक्ष या घटना के सम्बन्ध में वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। सामान्यतः सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग बड़े पैमाने पर, लोगों से जानकारी हासिल करने के लिये किया जाता है। इस कार्य के लिये सम्बन्धित घटना या समस्या के बारे में प्रश्न पूछने के लिये एक निश्चित प्रश्नावली तैयार की जाती है।

आजकल भारत में विभिन्न गैर-शैक्षिक उद्देश्यों जिसमें चुनावों के परिणामों पर भविष्यवाणी, विभिन्न उत्पादों की बिक्री पर बाजार रणनीति और विभिन्न सामाजिक विषयों पर लोगों की राय जानने जैसे कार्यों के लिये इस पद्धति का प्रयोग बढ़ रहा है।

4

**विशेष कथन :**

- (i) उपरोक्त अंकित Model-Answers केवल संकेत मात्र हैं। परीक्षार्थी इनके अतिरिक्त भी सही उत्तर लिख सकता है। परीक्षार्थी के हित में अनदेखी न करें।
- (ii) प्रश्न संख्या 20 व 21 आठ-आठ अंकों के हैं जिनका मूल्यांकन उप-परीक्षक स्व-विवेक से अथवा मुख्य परीक्षक की सहायता से करेंगे।
-